Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार-सम्मान घोषित 3
- राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारतीय राजनयिक मिशनों में शामिल होगा उत्तर प्रदेश 5
- जीआईएस-23 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर बना सिंगापुर 5
- मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 में जीता कांस्य पदक 6
- जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता कांस्य पदक 6
- आईटीआई को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार 7
- पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन 7
- दीनापुर में बनेगी पानी की जाँच की लैब 8
- उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित 8
- 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति 9
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली-2022 को दी मंज़ूरी 9
- लखनऊ में शुरू होगी देश की पहली नाइट सफारी 10
- उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंज़ूरी 10
- काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का कॉरिडोर 11
- देवरिया के खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 11
- काशी की तरह प्रयाग में भी चलेंगे क्रूज, संगम पर बनेगा हेलीपोर्ट 12
- यमुना किनारे बनेंगे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 12
- 2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला: एनसीआरबी रिपोर्ट 13

नोट :

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वर्ष 2021 के पुरस्कार-सम्मान घोषित

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वर्ष 2021 के सम्मान और पुरस्कार की घोषणा गई। संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से विद्वानों के नामों का चयन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- संस्थान का सर्वोच्च सम्मान 'भारत भारती' दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के पूर्व प्रोफेसर डॉ. रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया। भारत भारती सम्मान के तहत दी जाने वाली सम्मान राशि 8 लाख रुपए है। सम्मान सूची में लखनऊ से डॉ. ओ.पी. मिश्रा व हृदय नारायण दीक्षित समेत 18 साहित्यकारों के नाम शामिल हैं।
- संस्थान की ओर से पाँच लाख रुपए की राशि वाले सम्मान की श्रेणी में लोहिया साहित्य सम्मान देहरादून (उत्तराखंड) के बुद्धिनाथ मिश्र को, गुरुग्राम (हरियाणा) से डॉ. गिरिराज शरण अग्रवाल को हिन्दी गौरव सम्मान, नंदुरबार (महाराष्ट्र) के डॉ. विश्वास किसान पाटिल को महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के डॉ. रामशरण गौड़ को पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, लखनऊ के डॉ. ओम प्रकाश मिश्र को अवंती बाई साहित्य सम्मान, लखनऊ के हृदय नारायण दीक्षित को अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान के लिये चुना गया है।
- संस्थान की ओर से साहित्य भूषण सम्मान के लिये 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। इस सम्मान के लिये निम्नलिखित साहित्यकारों का चयन किया गया है-
  - हितेश कुमार शर्मा, बिजनौर, उ.प्र.
  - डॉ. रघुवीर सिंह अरविंद, अलीगढ़, उ.प्र.
  - डॉ. प्रीति श्रीवास्तव कबीर, लखनऊ, उ.प्र.
  - किशन स्वरूप, मेरठ, उत्तर प्रदेश
  - डॉ. उमाशंकर शुक्ल शितिकंठ, लखनऊ
  - डॉ. नताशा अरोड़ा, नोएडा, उ.प्र.
  - जयप्रकाश शर्मा जनकवि प्रकाश, प्रयागराज, उ.प्र.
  - डॉ. अशोक कुमार शर्मा, लखनऊ, उ.प्र.
  - डॉ. दयानिधि मिश्र, वाराणसी, उ.प्र.
  - डॉ. सभापति मिश्र, प्रयागराज, उ.प्र.
  - डॉ. प्रमोद कुमार अग्रवाल, झांसी, उ.प्र.
  - शिवानंद सिंह सहयोगी, मेरठ, उ.प्र.
  - डॉ. नरेश मिश्र, रोहतक, हरियाणा
  - डॉ. रूपसिंह चंदेल, धारुहेड़ा, हरियाणा
  - डॉ. सुशील सरित, आगरा, उ.प्र.

नोट :

- शची मिश्र, पुणे, महाराष्ट्र
- विजयशंकर मिश्र भास्कर, सुल्तानपुर, उ.प्र.
- गिरीश पंकज, रायपुर, छत्तीसगढ़
- शिवदयाल, पटना, बिहार
- डॉ. नीरजा माधव, वाराणसी, उ.प्र.

- 2.5 लाख रुपए की सम्मान राशि वाले पुरस्कार
  - लोकभूषण- डॉ. महेंद्र भनावत, उदयपुर, राजस्थान
  - कलाभूषण- डॉ. हृदय गुप्त, कानपुर, उ.प्र.
  - विद्या भूषण- विजय चितौरी, प्रयागराज, उ.प्र.
  - पत्रकारिता भूषण- बलबीर पुंज, नोएडा, उ.प्र.
  - प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण- डॉ. नलिनी बलबीर, पेरिस (फ्राँस)
  - हिन्दी विदेश प्रसार- कल्पना लालजी, मॉरीशस
  - बाल साहित्य भारती सम्मान- डॉ. फकीरचंद शुक्ला, लुधियाना (पंजाब)
  - डॉ. दिनेश पाठक शशि, मथुरा, उ.प्र.
  - मधुलिमये साहित्य सम्मान- डॉ. विक्रम सिंह, आगरा, उ.प्र.
  - पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान- अश्विनी कुमार दुबे, इंदौर, मध्य प्रदेश
  - विधि भूषण सम्मान- सुधा अवस्थी, प्रयागराज, उ.प्र.
- सौहार्द्र सम्मान: (राशि 2.50 लाख रुपए)
  - मुहीउद्दीन हसन सुहैल काकोरवी, लखनऊ (उर्दू)
  - डॉ. आर. लक्ष्मीनारायण, बंगलूरू, कर्नाटक (कन्नड़)
  - क्रांति कनाटे, बड़ोदरा, गुजरात (गुजराती)
  - डॉ. वीणा गुप्ता, जम्मू (डोगरी)
  - एस. अनंतकृष्णन (तमिल)
  - डॉ. यम लक्ष्मणाचार्युलु, हैदराबाद, तेलंगाना (तेलुगू)
  - मोहन सपरा, जालंधर, पंजाब (पंजाबी)
  - रामकृष्ण विनायक सहस्त्रबुद्धे, नागपुर, महाराष्ट्र (मराठी)
  - प्रोफेसर के.एस. सोमनाथन नायर, (मलयालम)
  - डॉ. हजारीमयुम इबेयाइमा देवी (मणिपुरी)
  - डॉ. मुरारीलाल अग्रवाल, गाजियाबाद, (संस्कृत)
  - राघू मिश्र, राउरकेला, ओडिशा, (ओड़िया)
  - डॉ. तुलसी देवी, फिरोजाबाद, उ.प्र. (सिंधी)
- एक लाख रुपए के पुरस्कार
  - मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान
  - डॉ. योगेंद्र प्रताप सिंह, लखनऊ
  - डॉ. प्रत्यूष दुबे, गोरखपुर

नोट :

- सम्मान के अलावा वर्ष 2021 में प्रकाशित 35 पुस्तकों पर 75 हज़ार रुपए के नामित पुरस्कार भी घोषित किये गए हैं-
  - 40 हज़ार रुपए पुरस्कार राशि वाले सर्जना पुरस्कारों के लिये 34 पुस्तकों का चयन किया गया है।
  - हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान लखनऊ के राहुल द्विवेदी को दिया गया है।
  - पं. बद्री प्रसाद शिंगलू स्मृति सम्मान लखनऊ की ही रजनी गुप्त को दिया गया है।

राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारतीय राजनयिक मिशनों में शामिल होगा उत्तर प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन) नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में भारतीय राजनयिक मिशन में शामिल होगा।

प्रमुख बिंदु

- अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन) नवनीत सहगल ने बताया कि यूपीओ ने अगले पाँच साल में राज्य से निर्यात को बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा है।
- यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर आदि में भारतीय दूतावास राज्य के प्रमुख वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के तहत पारंपरिक हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के उत्पादों को बढ़ावा देंगे।
- भारतीय राजनयिक मिशन दुनिया भर के प्रमुख निर्यात स्थलों में राज्य के पारंपरिक उत्पादों को बहुत ज़रूरी कर्षण और दृश्यता प्रदान करेंगे।
- महामारी की स्थिति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश का माल निर्यात 2020-21 में 07 लाख करोड़ रुपए से 30 प्रतिशत बढ़कर 2021-22 में 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिसमें से ओडीओपी टोकरी ने 72 प्रतिशत का योगदान दिया।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव सहगल ने बताया कि एमएसएमई विभाग ने पहले ही प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन के साथ राज्य के मर्चेंडाइज बास्केट के विपणन के लिये करार किया है और ई-बे के साथ भी इसी तरह का समझौता करेगा।
- उत्तर प्रदेश व्यापारिक निर्यात को बढ़ावा देने के लिये ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) चैनल का भी उपयोग करेगा। केंद्र द्वारा प्रचारित, ONDC को डिजिटल नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये अनिवार्य किया गया है। यह ओपन-सोर्स और ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल पर आधारित है, जो किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र है, इस प्रकार संस्थागत संस्थाओं के लिये एक विस्तृत बिक्री-खरीद अनुभव प्रदान करता है।
- सबसे अधिक बिकने वाले यूपी उत्पादों में चमड़े के सामान, कालीन, हाथ से बुने हुए वस्त्र, पीतल के बर्तन, काँच के बने सामान, खेल के सामान आदि शामिल हैं।
- ओडीओपी योजना, जिसे जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस समारोह के दौरान शुरू किया गया था, राज्य के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने और स्थानीय स्तर पर नौकरियाँ पैदा करने पर आधारित है।
- राज्य गैर-प्रदूषणकारी एमएसएमई उद्योगों के लिये जगह की बचत करने के लिये 'फ्लैटेड फैक्ट्री'की अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है। 'फ्लैटेड फैक्ट्री'एक बहुमंजिला औद्योगिक इमारत है, जिसमें औद्योगिक गोदामों के रूप में काम करने के अलावा, कई औद्योगिक और असेंबली इकाइयों को समायोजित किया जाता है।

जीआईएस-23 में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लोबल पार्टनर बना सिंगापुर

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि जनवरी में होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 (जीआईएस-23) में सिंगापुर उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बन गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अपने देश के गठबंधन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जनवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 के लिये सिंगापूर पहला भागीदार देश बन गया है।
- राज्य सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियों ने 250 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक का निवेश किया है। इसमें से अधिकांश निवेश राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के ज़िलों में है। हाल ही में आयोजित ग्राउंडब्रेकिंग समारोह में, सिंगापुर की कंपनियों ने 1,100 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शिखर सम्मेलन के लिये एक विस्तृत प्रचार योजना तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि यूके, यूएसए, कनाडा, यूएई, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड, इजराइल, फ्राँस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, मॉरीशस, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में रोड-शो के माध्यम से एक वैश्विक चर्चा पैदा की जा सके।

मेरठ की रूपल चौधरी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 में जीता कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 51.85 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही 17 वर्षीय रूपल चौधरी विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।
- इससे पहले 2 अगस्त को रूपल ने चार गुणा 400 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया था। भारतीय टीम ने तीन मिनट 17.76 सेकेंड का समय लेकर एशियाई जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय टीम अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर रही थी।
- वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में 51.50 सेकेंड के साथ ग्रेट ब्रिटेन की येमी मेरी ने स्वर्ण पदक, जबकि 51.71 सेकेंड के साथ केन्या की दमारिस मुतुंगा ने रजत पदक जीता।
- रूपल चौधरी ने चैंपियनशिप में दो बार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पहली बार सेमीफाइनल में उन्होंने 52.27 सेकेंड का समय निकाला और फिर फाइनल में इस समय में सुधार करते हुए 51.85 सेकेंड के साथ कांस्य पदक जीता।
- गौरतलब है कि इस साल के शुरू में रूपल ने राष्ट्रीय अंडर-20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिताब की प्रबल दावेदार कर्नाटक की प्रिया मोहन को पीछे छोड़कर महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था।

जैवलिन थ्रो में अन्नू रानी ने जीता कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2022 को बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स-2022 में मेरठ के बहादुरपुर गाँव की महिला भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने महिलाओं की जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया।

प्रमुख बिंदु

- अन्नू रानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंककर तीसरा स्थान हासिल किया। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की केलसे ली बार्बर ने 43 मीटर के थ्रो से स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन मैकेंजी लिटिल ने 64.27 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता।
- जैवलिन क्वीन के नाम से मशहूर अन्नू रानी कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स की जैवलिन इवेंट में यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश ही पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बन गईं हैं।

नोट :

- गौरतलब है कि अन्नू रानी से पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में काशीनाथ नायक और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में क्रमश: कांस्य और स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नायक ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में, जबकि चोपड़ा ने 2018 गोल्ड कोस्ट में पदक जीते थे।
- अन्नू रानी ने टोक्यो ओलंपिक-2021 में प्रतिभाग किया था, मगर वो पदक नहीं जीत पाई थीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप-2019 के फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। इसके अलावा अन्नू रानी ने एशियन चैंपियनशिप-2019 में रजत पदक, एशियन चैंपियनशिप-2017 में कांस्य पदक, साउथ एशियन गेम्स-2016 में रजत पदक और एशियन गेम्स-2014 में कांस्य पदक जीता है।

आईटीआई को अपग्रेड करेगी उत्तर प्रदेश सरकार

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार के उद्देश्य से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को अपग्रेड करने के अपने निर्णय की घोषणा की है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है।

प्रमुख बिंदु

- व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार आईटीआई के तकनीकी उन्नयन के लिये एक निजी संगठन के साथ समझौता करेगी।
- राज्य सरकार ने पहले चरण में, उन्नयन के लिये 50 आईटीआई का चयन किया गया है, जिसके लिये 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में छात्रों के रोज़गार कौशल में सुधार के लिये केंद्र शुरू किये जाएंगे। इसके लिये हर ज़िले में दो कॉलेज और राज्य भर के 150 कॉलेजों का चयन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में 10 नए आईटीआई स्थापित किये हैं, जहाँ प्रशिक्षण देने का काम जल्द ही शुरू होगा। इसके अलावा, 15 नए सरकारी आईटीआई का निर्माण पूरा हो चुका है और जल्द ही उनका उद्घाटन किया जाएगा।
- राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने 29 सेक्टरों की पहचान की थी, जिनमें दो लाख से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके अंतर्गत लगभग 10,000 युवाओं को उड्डयन में तथा 33,021 को स्वास्थ्य सेवा के लिये में प्रशिक्षित किया जाएगा।

पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी जलशक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जाँच में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर पहुँच गया है। उत्तर प्रदेश ने छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को पानी के सैंपल की जाँच में पीछे छोड़ दिया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि प्रदेश की महिलाओं ने 20,756 गाँव में 11,97,890 पानी के सैंपलों की जाँच पूरी कर ली है। एफटीके किट से की गई जाँच में 69,279 पानी के सैंपल दूषित पाए गए हैं। 12,919 जगह आवश्यक कार्रवाई की गई है।
- भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 17,823 गाँव में महिलाओं ने 11,60,940 पानी के सैंपल की जाँच की है और वह दूसरे स्थान पर है। एफटीके किट से पानी जाँच के मामले में तीसरे नंबर पर केरल, चौथे पर ओड़ीसा और पाँचवें स्थान पर मध्य प्रदेश है।
- राज्य सरकार की निरंतर निगरानी व नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की कार्ययोजना ने उत्तर प्रदेश के इस अभियान को नई रफ्तार दी है। कुछ दिनों पहले तक शीर्ष 10 से बाहर रहने वाले उत्तर प्रदेश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए देश में नंबर एक स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

नोट :

- जन-जन तक नल से शुद्ध पानी पहुँचाने के लिये राज्य सरकार ने प्रदेश भर के हर गाँव में पाँच-पाँच महिलाओं को पानी जाँच के लिये प्रशिक्षित करने का अभियान भी शुरू किया है।
- राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य के हर घर तक नल से जल पहुँचाने के साथ लोगों को शुद्ध पानी मुहैया कराना है।

दीनापुर में बनेगी पानी की जाँच की लैब

चर्चा में क्यों ?

11 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश के दीनापुर एसटीपी के यांत्रिक शाखा में पानी की जाँच के लिये प्रयोगशाला बनाने हेतु डेनमार्क के सात सदस्यीय दल ने दीनापुर एसटीपी का निरीक्षण किया व जल निगम के अधिकारियों के साथ चर्चा की।

प्रमुख बिंदु

- नार्डिक कॉरपोरेशन डेनमार्क के डेवलपमेंट मिनिस्टर के नेतृत्व में सात सदस्यीय दल ने दीनापुर एसटीपी में बने 140 एमएलडी प्लांट को देखा तथा वाराणसी के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में जानकारी ली।
- जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि लगभग 412 एमएलडी की क्षमता से सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। यह योजना 2030 तक के लिये है।
- नमामि गंगे के डीजी ने बताया कि डेनमार्क के लोग नई तकनीक से प्रयोगशाला बनाएंगे। इसमें सीवेज व पेयजल, दोनों की जाँच होगी।
- इसके अलावा डेनमार्क के प्रतिनिधिमंडल ने बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में कमिश्नर समेत प्रोफेसरों, पर्यावरणविदों व शोध छात्रों के साथ संवाद किया तथा गंगा और सहायक नदियों की साफ-सफाई के लिये किये जा रहे कार्यों पर चर्चा की।
- डेनमार्क के डेवलपमेंट कोऑपरेशन मिनिस्टर फ्लेमिंग मोलर मोर्टेसन और भारत में डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने, डेनमार्क फॉरेन अफेयर्स, स्थाई सचिव समेत सभी डेनिश डेलीगेट्स को गंगा-वरुणा पर किये जा रह शोधों की भी जानकारी दी गई।
- मिनिस्टर फ्लेमिंग मोलर मोर्टेसन ने कहा कि भारत और डेनमार्क पर्यावरण, नदी जल संरक्षण के क्षेत्र में पहली बार समझौता कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा की सफाई के लिये स्मार्ट रिवर लैबोरेटरी की स्थापना होगी।
- बीएचयू के पर्यावरण एवं धारणीय विकास संस्थान के निदेशक प्रो. एएस रघुवंशी ने वरुणा और अस्सी की स्थिति बताई। गंगा मित्र रोहित ने बताया कि प्रयागराज से बलिया तक गंगा के किनारे अमृत वन लगाए जाएंगे। इस बेल्ट में 15 हज़ार गंगा जल संरक्षक तैयार किये गए हैं। 15 ज़ोन, 15 गंगा कोआर्डिनेटर, 120 गंगा सब कोआर्डिनेटर, 1500 वर्किंग साइट्स और 1500 कंजर्वेशन सोसायटी बनाई गईं है।

उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये घोषित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
- इस सूची में सीबीआई के 15, एनआईए के 5, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 कर्मी और शेष अन्य राज्यों के हैं।
- इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में उत्तर प्रदेश पुलिस के उप-पुलिस अधीक्षक संसार सिंह राठी, उप-पुलिस अधीक्षक सविरतना गौतम, एसएचओ कमलेश सिंह, इंस्पेक्टर राम गोविंद मिश्रा, इंस्पेक्टर संतोष कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार, इंस्पेक्टर शैलेश कुमार राय, इंस्पेक्टर भैया शिवप्रसाद सिंह, सब-इंस्पेक्टर नीरज कुमार पाल और सब-इंस्पेक्टर सूरज कुमार तिवारी शामिल हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि अपराध की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की गई थी।
- इसके तहत किसी भी अपराध की जाँच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा व काम से असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को यह मेडल दिया जाता है।
- 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये पाँच पुलिस पदक शुरू किये थे। इसमें विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जाँच में उत्कृष्टता पदक शामिल हैं।

10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति

चर्चा में क्यों ?

14 अगस्त, 2022 को एमएसएमई के अपर मुख्य सचिव डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सेक्टरवार रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके तहत प्रदेश में आयात होने वाले 95 उत्पादों को चिह्नित किया गया है। इनका उत्पादन प्रदेश में ही करने की योजना बनाई गई है।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एमएसएमई विभाग को प्रदेश में आयात होने वाले उत्पादों को चिह्नित करने के निर्देश दिये थे।
- वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी के ड्राई पोर्ट (रेल या सड़क परिवहन से बंदरगाह का जुड़ना) से 55 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक के 95 उत्पाद आयात हुए हैं। इसमें 10 हज़ार करोड़ रुपए से लेकर सौ करोड़ रुपए तक के 48 उत्पादों का आयात किया गया है।
- प्रदेश में आयात होने वाले शीर्ष-10 उत्पादों में पहले स्थान पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के 10,200 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर, जेनरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, सेमी कंडक्टर चिप, प्रोसेसर और मेमोरीज आदि उत्पाद हैं। दूसरे स्थान पर 6592 करोड़ रुपए के मछली का तेल, कैस्टर ऑयल, सोयाबीन का तेल व अन्य खाद्य तेल हैं।
- तीसरे स्थान पर 6315 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स और बड़े प्लांट में उपयोग होने वाली मशीनरी, चौथे स्थान पर 4906 करोड़ रुपए के प्लास्टिक पैलेट्स और पाँचवें स्थान पर 2817 करोड़ रुपए के एल्यूमीनियम, आयरन, स्टील और कॉपर के उत्पाद हैं।
- छठे स्थान पर 1592 करोड़ रुपए के ऑर्गेनिक केमिकल्स, सातवें स्थान पर 1590 करोड़ रुपए के सर्जिकल उपकरण, आठवें स्थान पर 1515 करोड़ रुपए के सोने-चांदी के आभूषण व रत्न, नौवें स्थान पर 1207 करोड़ रुपए के पेपर बोर्ड, कार्ड बोर्ड, केमिकल के बने हार्ड बोर्ड और दसवें स्थान पर 1106 करोड़ रुपए के निकिल व निकिल स्क्रैप मेटल्स का आयात होता है।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली-2022 को दी मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल शुल्क नियमावली-2022 को मंज़ूरी दी। इसके तहत अब विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में भवन निर्माण के लिये नक्शा पास कराने के लिये 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जल शुल्क देना होगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पहले यह जल शुल्क लखनऊ और बनारस में नहीं लिया जाता था, लेकिन अब वहाँ के लोगों को भी इसका भुगतान करना होगा।
- नियमावली के मुताबिक ले-आउट प्लान के मामलों में जल शुल्क भूमि के कुल क्षेत्रफल के हिसाब से लिया जाएगा। बहुमंजिला भवन निर्माण पर सभी तलों व बेसमेंट को शामिल करते हुए कुल क्षेत्रफल के आधार पर इसे वसूला जाएगा।

नोट :

- मौजूदा निर्मित क्षेत्र से अतिरिक्त निर्माण करने पर भी जल शुल्क देय होगा। जल शुल्क की दरों को हर साल एक अप्रैल से आयकर विभाग के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा।
- विकास प्राधिकरण, योजना के बाहर या जहाँ वह जलापूर्ति करने में असमर्थ होगा, वहाँ जल शुल्क देय नहीं होगा। वैधता अवधि के अंदर स्वीकृति के लिये प्रस्तुत पुनरीक्षित मानचित्र, जिसके लिये जल शुल्क पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- वैधता अवधि बढ़ाने की स्थिति में पूर्व में जमा शुल्क को समायोजित करते हुए नक्शा पास करने की तिथि से लागू दर पर शुल्क लिया जाएगा। वैधता अवधि के उपरांत पेश नक्शों के लिये पूर्व में जमा शुल्क के समायोजन के बाद उसके पास होने की तिथि से लागू दर पर जल शुल्क देय होगा।
- जल शुल्क 10 लाख रुपए तक होने पर एकमुश्त भुगतान करना होगा। इससे अधिक होने पर 10 लाख रुपए का भुगतान एकमुश्त और शेष को चार अर्द्धवार्षिक किस्तों में 9% ब्याज के साथ लिया जाएगा। इसके लिये बकाया राशि के समतुल्य बैंक गारंटी भी देनी होगी या उतने मूल्य की विक्रय योग्य भूमि प्राधिकरण के पक्ष में गिरवी रखनी होगी। शेष राशि का भुगतान होने पर बैंक गारंटी या बंधक भूमि छोड़ दी जाएगी। किश्तों के भुगतान में देरी पर 9% वार्षिक ब्याज के साथ 0 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से दंड ब्याज लिया जाएगा।

लखनऊ में शुरू होगी देश की पहली नाइट सफारी

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजधानी लखनऊ में देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस बारे में पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सिंगापुर की विश्व की पहली नाईट सफारी की तर्ज़ पर 2027.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुकरैल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में नाईट सफारी विकसित की जाएगी और 150 एकड़ में प्राणि उद्यान बनाया जाएगा।
- यह नाइट सफारी बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज़ पर विकसित होगी, जहाँ टाइगर, तेंदुआ और भालू के लिये अलग-अलग सफारी बनाई जाएंगी। लखनऊ के ऐतिहासिक नवाब वाज़िद अली शाह प्राणि उद्यान को वर्तमान जगह से हटाकर नाइट सफारी में शिफ्ट किया जाएगा। कुकरैल नदी को खूबसूरत रिवरफ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। नाइट सफारी में टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी।
- गौरतलब है कि देश की यह पहली नाइट सफारी होगी। वर्तमान में देश में 13 ओपन डे सफारी हैं, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है।
- नाइट सफारी का प्रवेश द्वार भव्य एवं आकर्षक होगा। यहाँ व्याख्या केंद्र, बटरफ्लाई इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की योजना है।
- वन्य जीव बाड़े में न रखकर खुले आकाश में केटल ग्रिड में रखे जाएंगे। यहाँ एक ओपन एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा, जो केवल रात में खुलेगा। सफारी में रात में जानवरों के लिये चंद्रमा की रोशनी की तरह मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। दिन में पर्यटकों के लिये आधुनिक थीम पार्क बनाया जाएगा।
- विश्वस्तरीय सुविधाओं के तहत नाइट सफारी में स्थानीय गाइड के साथ ट्रेन की सवारी और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। इसके अलावा कैनोपी वाक, कैंपिंग गतिविधि, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोहण, ट्री टॉप रेस्टोरेंट, नेचर ट्रेल और फूड कोर्ट आदि सुविधाएँ विकसित की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के वन अभयारण्यों के बाहर अनुमेय क्षेत्र में पर्यटन अवसंरचना सुविधाओं के विकास एवं प्रबंधन के लिये उत्तर प्रदेश ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड (UP Eco-Tourism Development Board) के गठन के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ईका-टूरिज्म बोर्ड का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे।
- इस बोर्ड में 10 विभागों (पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन) को शामिल किया गया है।
- बोर्ड की संरचना में ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड तथा ईको-टूरिज्म कार्यकारी समिति रहेगी। कार्यकारी समिति पर्यावरण पर्यटन विकास बोर्ड के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्रवाई हेतु ज़िम्मेदार होगी।
- इको-टूरिज्म विकास बोर्ड ट्रैकिंग, हाइकिंग, साइकलिंग, कारवां टूरिज्म, सीप्लेन और रिवर क्रूज, एडवेंचर टूरिज्म के साथ-साथ होटल, रिसॉर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं, बैलूनिंग, जंगल कैंपिंग और ईको-पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये कल्याण पर्यटन, जैसे– आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की सुविधा प्रदान करेगा।
- विकास बोर्ड के सदस्य दो प्रकार के होंगे। इनमें शासकीय (पदेन) सदस्य एवं विशेष आमंत्री सदस्य रहेंगे। कृषि मंत्री, वन मंत्री, आयुष मंत्री, वित्त मंत्री, पर्यटन मंत्री, सिंचाई मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वन निगम के एमडी बोर्ड के सदस्य रहेंगे।
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन इसके समन्वयक की भूमिका में होंगे।
- आईआरसीटीसी के प्रतिनिधि, सशस्त्र सीमा बल उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के प्रतिनिधि, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी के प्रतिनिधि, कछुआ कंजर्वेशन फंड के प्रतिनिधि, कतर्नियाघाट फाउंडेशन के प्रतिनिधि, पाँच नामित पर्यावरण एवं पर्यटन विशेषज्ञ विशेष आमंत्री होंगे। इसके अलावा विशेष आमंत्री के रूप में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली दो अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थाओं का चयन प्रत्येक दो वर्ष के लिये किया जाएगा।

काशी विश्वनाथ की तर्ज पर बनेगा ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का कॉरिडोर

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को मथुरा जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मथुरा ज़िला प्रशासन ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला दर्शन के दौरान बांकेबिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते दो श्रद्धालुओं की मौत के बाद काशी विश्वनाथ की तर्ज़ पर बांकेबिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने जाने का प्रस्ताव बनाया है।

प्रमुख बिंदु

- वृंदावन में बिहारीजी कॉरिडोर से ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर का स्वरूप बदल जाएगा। कॉरिडोर बनने से संकरी गलियों से श्रद्धालुओं को मुक्ति मिलेगी, साथ ही जनसुविधाएँ भी मुहैया हो सकेंगी। नवनिर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को वृंदावन के लिये आधार बनाया जा रहा है।
- गौरतलब है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल करीब पाँच लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के दायरे में 23 इमारत और 27 मंदिर भी आते हैं। चार बडे+ गेट हैं, कॉरिडोर में 22 शिलालेखों पर काशी की महिमा का वर्णन किया गया है।
- इस कॉरिडोर में मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, कई यात्री सुविधा केंद्र, यूटिलिटी भवन सहित आदि सुविधाएँ दी गई हैं। 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर के बाद काशी मंदिर को भव्यता कॉरिडोर के माध्यम से दी गई है।
- इसके अलावा दक्षिण भारत स्थित रामेश्वरम् मंदिर का कॉरिडोर सबसे बड़ा है, जो करीब 400 फीट लंबा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल रामेश्वरम् के लिये बने कॉरिडोर की खूबसूरती वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इस कॉरिडोर की चौड़ाई 197 मीटर तक है।

नोट :

देवरिया के खुर्शीद अहमद राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें उत्तर प्रदेश के खुर्शीद अहमद का नाम भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिये दिया जाएगा। वह देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा में शिक्षक हैं। प्रदेश के बेसिक व माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों में अकेले इनका चयन हुआ है।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

काशी की तरह प्रयाग में भी चलेंगे क्रूज, संगम पर बनेगा हेलीपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और प्रयागराज मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के पूर्व ही वाराणसी की तर्ज़ पर यहाँ भी क्रूज की सेवाएँ और जलमार्ग से यातायात का परिवहन शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि कुंभ से पहले संगम पर जो हेलीपोर्ट बनाया जाएगा, उसके ज़रिये प्रयागराज से जल परिवहन भी शुरू होगा। गंगा एक्सप्रेस-वे दिल्ली सहित अन्य ज़िलों से प्रयागराज की पहुँच को और सुगम बनाएगा।
- राज्य सरकार की योजना प्रयागराज से वाराणसी तक क्रूज परिवहन प्रारंभ करने की है। गौरतलब है कि प्रदेश में अवस्थित पौराणिक शहर वाराणसी में पहले से ही क्रूज सेवा प्रारंभ की जा चुकी है।
- यह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (प्रयागराज से हल्दिया तक) का भी मार्ग है, अत: भविष्य में मालवहन के अतिरिक्त यहाँ से जलमार्ग का प्रयोग आमजन के परिवहन के लिये भी किया जा सकेगा।
- मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि रेलवे द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित किये जा चुके कर्ज़न ब्रिज को धरोहर के रूप में पर्यटकों के लिये विकसित किया जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रयागराज से अयोध्या व लखनऊ रेलमार्ग पर गंगा नदी पर बने कर्ज़न ब्रिज की आयु 117 वर्ष है। रेल यातायात के लिये यह पुल 15 जून, 1905 को खोला गया था। तब इस रेलखंड का संचालन अवध व रुहेलखंड रेलवे करती थी। इस पुल से सड़क यातायात 20 दिसंबर, 1905 को शुरू हुआ था। वर्ष 1998 में इस पुल से सड़क और रेल यातायात बंद कर दिया गया था।

नोट :

यमुना किनारे बनेंगे हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यमुना नदी में गिर रहे बड़े नालों के कारण बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- 583 करोड़ रुपए की लागत से यमुना नदी के किनारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, जो यमुना में गिर रहे 6 एमएलडी सीवर का ट्रीटमेंट (शोधन) करेंगे।
- इस संबंध में दिल्ली में एनएमसीजी उत्तर प्रदेश जल निगम और विश्वराज एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू (समझौता ज्ञापन) साइन किया गया है। करार पर जलनिगम के अधीक्षण अभियंता राजकुमार शर्मा, विश्वराज एनवायरमेंट के सत्यजीत राउत और एनएमसीजी प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद कुमार ने हस्ताक्षर किये।
- गौरतलब है कि यमुना में नाले के पानी के कारण उपजे दलदल से आगरा में ताज़महल पर गोल्डी काइरोनोमस कीड़ों का हमला हो रहा है। बीते चार साल से ताज़महल पर कीड़ों का हमला बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्वत: संज्ञान लेने के बाद भी यमुना नदी में सीवर गिरना बंद नहीं हुआ है।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार ने बताया कि नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण से यमुना में बिना ट्रीटमेंट के सीवर का गिरना बंद हो जाएगा।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीवर समस्याओं के समाधान के लिये तीन नए एसटीपी के निर्माण के साथ इंटरसेप्शन, डायवर्जन स्ट्रक्चर, आईएंडडी नेटवर्क बिछाने, 15 साल के लिये ऑपरेशन एंड मेंटीनेंस को भी शामिल किया।

2021 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का सिर्फ एक मामला: एनसीआरबी रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के 2021 के क्राइम के आँकड़ों के अनुसार पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज हुए हैं, उसमें से उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामलों में महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77, बिहार में 51, हरियाणा में 40 मामले दर्ज हुए हैं, वहीं इस मामले में राजस्थान पाँचवें नंबर पर है।
- नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में राज्य में पहले से काफी कमी आई है। देश की तुलना में साइबर क्राइम की घटनाओं में भी प्रदेश में कमी देखने को मिल रही है।
- एनसीआरबी के जारी आँकड़ों के अनुसार साल 2019 में बच्चों के खिलाफ 18943 मामले दर्ज किये गए, जबकि साल 2021 में यह घटकर 16838 हो गए। साल 2019 में राज्य में महिलाओं के खिलाफ 59853 मामले दर्ज किये गए जो 2021 में घटकर 56083 हो गए। इतना ही नहीं 2019 में साइबर क्राइम के 11416 मामले दर्ज किये गए जो साल 2021 में घटकर 8829 हो गए।
- साल 2019 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2 फीसदी की कमी, बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में 11.11 फीसदी की कमी और साइबर क्राइम के मामले में भी 22.6 फीसदी की कमी देखने को मिली है।
- रिपोर्ट के अनुसार, देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश 16,838 मामलों में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध में 28वें स्थान पर, फिरौती के लिये अपहरण में 50 मामलों के साथ 36 वें स्थान पर और पाक्सो एक्ट के मामले में 6.3 क्राइम रेट के साथ 21वें स्थान पर रहा।
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में गिरावट की प्रवृत्ति भी जारी रही, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में प्रदेश देश में 16वें स्थान पर है। दुराचार के 2845 मुकदमों के साथ राज्य 23वें स्थान पर और हत्या में 24वें स्थान पर रहा।

नोट :